

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-3) विभाग

10

क्रमांक: प.9(5)(9)कार्मिक/क-3/2001

जयपुर, दिनांक 16, 2002

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विश्लिष्ट शासन सचिव  
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर सहित)

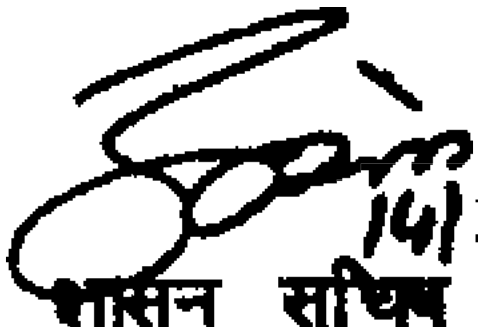
परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20/3/2001 को समस्तस्यक परिपत्र के माध्यम से राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम-18 के प्रावधान, जिसके तहत कोई भी राजकर्मि बिना पूर्व अनुमति के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निजी रूप से व्यवसाय एवं नियोजन प्राप्त नहीं कर सकेगा तथा अपनी पत्नी या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा धारित (owned) अथवा संचालित (managed) बीमा एजेन्सी अथवा अन्य कमीशन एजेन्सी या इस प्रकार के किसी अन्य व्यवसाय में पक्ष-प्रचार (canvassing) भी नहीं कर सकेगा, की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह ब्यदिष्ट किया गया था कि राजकर्मि इस प्रकार के व्यावसायिक कृत्य व अन्य कमीशन एजेन्सी के पक्ष-प्रचार में लिप्त न हों अन्यथा इसे आचरण नियमों का उल्लंघन मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि उक्त नियमों व निर्देशों के बावजूद कुछ राजकर्मि उपर्युक्त कथित व्यावसायिक गतिविधियों में रुचि लेकर उसके प्रचार/प्रसार के दृष्टिकोण से सरकारी दौरो के माध्यम से अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पदीय हैसियत का प्रभाव डाल कर उनको उपरोक्त प्रकार की व्यावसायिक कम्पनी/एजेन्सी आदि का सदस्य बनाने अथवा उस कम्पनी के उत्पाद को स्वीदने हेतु मजबूर करते हैं।

अतः सभी संबंधित को पुनः ब्यदिष्ट किया जाता है कि राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के प्रावधानों व इस संबंध में जारी निर्देशों की कठोरता से पालना की जाय तथा कोई भी अधिकारी/कर्मचारी सरकारी दौरो के माध्यम से अथवा अन्यथा किसी भी प्रकार से अपने अधीनस्थ राजकर्मियों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पदीय हैसियत का प्रभाव डालकर उन्हें किसी प्रकार की व्यावसायिक कम्पनी/एजेन्सी आदि का सदस्य बनाने अथवा उस कम्पनी के उत्पाद को स्वीदने हेतु प्रेरित करने जैसी कार्यवाही न करें अन्यथा इसे आचरण नियमों का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

कृपया आचरण नियमों के उक्त प्रावधान तथा निर्देश अपने अधीन समस्त राजकर्मियों के ध्यान में लाना सुनिश्चित करें।

  
14/5/2002  
शासन सचिव